Work Plan with the Russian Academy of Agricultural Sciences (RAAS), Russia on 25.11.1997 for cooperation in agricultural research ande allied subjects. The Work Plan aims at scientific and technical cooperation, exchange of information and materials between both the countries through coordination and conducting a joint research projectoral trials that may be mutually identified and by organizing bilateral Workshops and Seminars on topics of mutual interest.

The Work P-lan is likely to be implemented by 31.12.1999.

Area Under Fodder Crops

1707. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it would be economically more appropriate to increase area under fodder crops to ensure healthier cattle;

(b) whether the economics of enhanced fodder cultivation and the dairy sector has been worked out;

(c) what would be the ideal ratio of dairy and cereals production in the agricultural sector;

(d) whether any efforts are underway to achieve this ideal production ratio of dairy products and cereals; and

(e) if so, details of specific plans?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) The economic of fodder production and dairy sector has been worked out. The cost-benefit ratio ranges from 1.5 to 3.0 in different fodder cropping system.

(c) There is no systematic study to find out the ideal production ratios of dairy production and cereals.

(d) and (e) Questions do not arise.

Post of Animal Husbandry Commissioner

1708. DR. ARUN KUMAR SARMA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the reasons for keeping the post of Animal Husbandry Commissioner vacant indicating the period of such vacancy and action initiated to fill up the post;

(b) whether the A.H. Commissioner is the chairperson of Indian Chapter of WWF;

(c) if so, the compelling grounds for such long deferment; and

(d) status of the proposal towards formation of Indian Council of Veterinary Research?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) Filling up of the post of Animal Husbandry Commissioner has always been under the active consideration of the Government and the Union Public Service Commission have now recommended a candidate for appointment to the post of Animal Husbandry Commissioner.

The Central Government is not involved in the functioning of WWF.

(d) No decision has yet been taken to set up Indian Council of Veterinary Research under this Department.

उड़ीसा के सूखा प्रभावित लोगों के लिए योजनाएं

1709. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कई वर्षों से उड़ीसा में सूखे व भुखमरी की स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन-कौन से हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इनमें अनुमानत: कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या सूखे व भुखमरी की स्थिति का आकलन करने के लिए केन्द्र सरकार के प्राधिकारियों ने कभी राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य में इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाएं कार्यान्वित करने हेतु कितनी सहायता उपलब्ध करवाई गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य में सूखे की स्थिति बनी रही। राज्य सरकार ने जांच की थी ता यह सुनिश्चित किया था कि इस प्रकार से घटित मृत्यु की घटनायें भुखमरी के कारण नहीं हुई।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1996 के दौरान 28 जिलों में 28837 गांव तथा 1997 के दौरान 16 जिलों में 4688 गांव सूखे से प्रभावित हुये। वर्ष 1998 के दौरान प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार 24 जिलों में 11192 गांवों तथा 62 वार्डों में 50% या इससे अधिक फसल हानि होने की सूचना मिली है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दलों ने दिसम्बर, 1996 तथा अक्तूबर, 1998 में राज्य का दौरान किया था। एक अन्य केन्द्रीय दल ने बोलांगीर तथा सोनीपुर जिलों में कथित भुखमरी से मृत्यु के मामलों की जांच करने के लिये दिसम्बर, 1998 में इन जिलों का दौरा किया था।

(घ) कालाहांडी-बोलांगीर-कोरापुट जिलों में स्थायी समाधान के लिये उपाय के तौर पर एक दीर्घकालीन कार्य-योजना तैयार की गई है। आपातकालीन अहार कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य ने वृद्ध पेंशन योजना, विशेष पोषण कार्यक्रम, मध्य-दिवस अहार कार्यक्रम, केयर फीडिंग के तहत लाभानुभोगियों की संख्या में वृद्धि की है। जल जमाव की संरचनाओं का निर्माण, डीजल पम्पसेटों की आपूर्ति, पेय जल की समस्या को हल करने के लिये सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में ट्यूब वेल तथा सिंचाई व पेय जल के उद्देश्यों के लिये गहर ट्यूब वेल तथा नये एल०आई० पाइन्ट की स्थापना करने के लिये भी योजनायें तैयार की गई हैं।

(ङ) 1996-97 के दौरान सूखे की स्थिति में आपदा राहत कोष के तहत वार्षिक आबंटन के अलावा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 50 करोड़ रु० की सहायता तथा 1997-98 के दौरान आपातकालीन अहार कार्यक्रम के लिये राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 4.00 करोड़ रु० की सहायता दी गई थी। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 445.59 करोड़ रु० की सहायता के संबंध में राज्य सरकार के अनुरोध पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा रहा है।

New Agricultural Policy

1710. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have finalised a new agricultural policy;

(b) if so, what are the details in terms of redeeming features and new infrastructure institutional network proposed/existing network to be strengthened/upgraded, State-wise; and

(c) details of action plan proposed by the Agricultural and Processed Foods Export Development Authority (APEDA) under New agricultural policy with reference to Maharashtra in particular?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The draft National Policy on Agricultur is in the final stages of drafting.

(c) The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority proposes to set up (i) cold storage and cargo handling facility at Mumbai Airport; and (ii) wholesale market cum auction centre for flowers in Mumbai.

Post of ESA in Department of Agriculture and Cooperation

1711. SHRI C.O. POULOSE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the post of Economic and Statistical Adviser (ESA) of the Department of Agriculture and Cooperation was advertised long back;

(b) whether the present incumbent of the post of Economic and Statistical Adviser (ESA) has already got two extensions, after completion of five years terms;

(c) whether giving extension after six years on a deputation post is against Department of Personnel and Training (DoPT) rules; and

(d) whether the deputation of ESA will be terminated after six years; if not the reasons therefor and the details thereof?